

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन INDIAN NATIONAL MOVEMENT

SOME IMPORTANT AND REPEATED TOPICS FOR YOUR EXAM

BOTH HINDI AND ENGLISH

PART 1 DECEMBER SESSION

Write a note on the Quit India Movement.

The **Quit India Movement**, also known as the **Bharat Chhodo Andolan**, was a significant movement launched by the **Indian National Congress** during the **Second World War** in 1942. It was aimed at demanding an immediate end to British rule in India.

The movement was a response to the British refusal to grant India full independence and the growing discontent due to the hardships faced by Indians during the war. It marked a critical turning point in the Indian independence struggle and led to widespread protests and resistance against British authority across the country.

भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे **क्रिट इंडिया मूवमेंट** के नाम से भी जाना जाता है, 1942 में **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था।

इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। यह आंदोलन ब्रिटिशों द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने से इंकार करने और युद्ध के दौरान भारतीयों को होने वाली कठिनाइयों के कारण उत्पन्न असंतोष का परिणाम था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विरोध और प्रतिरोध को जन्म दिया।

1. Cause of the Movement:

- The Quit India Movement was primarily triggered by the British refusal to grant India independence after the **Cripps Mission** in 1942, which failed to meet Indian expectations. During the Second World War, Britain asked India to support its war effort without offering any concrete political concessions in return. The demand for an immediate end to British rule became urgent as India's economic and social conditions worsened.
- **आंदोलन के कारण:**
 - भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से 1942 में **क्रिप्स मिशन** द्वारा भारत को स्वतंत्रता देने से इनकार करने के बाद शुरू हुआ, जो भारतीयों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटेन ने भारत से युद्ध प्रयासों में सहयोग करने के लिए कहा, लेकिन बदले में कोई ठोस राजनीतिक रियायत नहीं दी। ब्रिटिश

शासन को तुरंत समाप्त करने की मांग और भी ज़्यादा तीव्र हो गई जब भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ खराब हो गईं।

2. Launch of the Movement:

- On **August 8, 1942**, the Indian National Congress, led by **Mahatma Gandhi**, passed a resolution calling for the immediate withdrawal of British rule from India. The movement was launched from the historic **Bombay session** of the Indian National Congress. Gandhi gave the famous slogan "**Do or Die**" to inspire the masses to fight for independence.
- **आंदोलन की शुरुआत:**
 - **8 अगस्त 1942** को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने **महात्मा गांधी** के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत से ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक **मुंबई सत्र** से शुरू हुआ। गांधी ने जनमानस को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रसिद्ध नारा "**करो या मरो**" दिया।

3. Repression by the British Government:

- The British government responded with immediate repression. Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, and other leaders were arrested and imprisoned. The Congress was declared illegal, and its offices were closed down. Protests, strikes, and demonstrations broke out across India, and the British used force to suppress these movements.
- **ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन:**
 - ब्रिटिश सरकार ने तुरंत दमनात्मक उपाय अपनाए। गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और इसके कार्यालयों को बंद कर दिया गया। भारत भर में विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और धरने शुरू हो गए, और ब्रिटिशों ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया।

4. Mass Participation:

- Despite the arrests and repressive measures, the movement saw massive participation from people across India, including students, workers, farmers, and women. The movement spread rapidly in urban and rural areas, with people defying curfews and participating in protests. However, it was largely leaderless after the arrest of major leaders.
- **जनसामान्य की भागीदारी:**
 - गिरफ्तारियों और दमनात्मक उपायों के बावजूद, इस आंदोलन में भारत के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने भाग लिया, जिसमें छात्र, श्रमिक, किसान और महिलाएं शामिल थीं। यह आंदोलन शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैला, लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते थे। हालांकि, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन अधिकतर बिना नेतृत्व के था।

5. Impact and Legacy:

- The Quit India Movement failed to immediately achieve its objective of ending British rule, but it had a profound impact on the freedom struggle. It made it clear that the majority of Indians were no longer willing to accept British rule. The British realized that they could no longer govern India with the same ease, and it accelerated the demand for independence.
- **प्रभाव और धरोहर:**
 - भारत छोड़ो आंदोलन ने तत्काल ब्रिटिश शासन समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव डाला। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीयों का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ब्रिटिशों ने यह महसूस किया कि वे अब भारत पर पहले जैसे आसानी से शासन नहीं कर सकते, और इससे स्वतंत्रता की मांग को और तेज़ी मिली।

Discuss the demand for Pakistan and its consequences.

The **demand for Pakistan** was a pivotal moment in the history of India's struggle for independence. It was primarily driven by the growing sense of political, cultural, and religious differences between the Muslim and Hindu communities, particularly under the leadership of the **All India Muslim League** and its prominent leader, **Muhammad Ali Jinnah**. The demand for a separate Muslim-majority nation emerged during the 1940s, amidst rising communal tensions and the inability of the Indian National Congress and the British to address the aspirations of Muslims. This ultimately led to the **partition of India** in 1947, with the creation of **Pakistan** as a separate nation for Muslims.

पाकिस्तान की मांग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह विशेष रूप से **ऑल इंडिया मुस्लिम लीग** और इसके प्रमुख नेता **मुहम्मद अली जिन्ना** के नेतृत्व में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ती राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नताओं द्वारा प्रेरित था। एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र की मांग 1940 के दशक में उभरी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिशों द्वारा मुसलमानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थता के कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, 1947 में **भारत का विभाजन** हुआ और **पाकिस्तान** को मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया।

1. Origins of the Demand for Pakistan:

- The demand for Pakistan can be traced back to the **Two-Nation Theory**, proposed by **Sir Syed Ahmed Khan** in the 19th century, which argued that Hindus and Muslims were two distinct nations with different religions, cultures, and social customs. The theory gained significant traction in the early 20th century, especially after the **Lucknow Pact** of 1916, when political cooperation between Hindus and Muslims was seen as a temporary arrangement.
- पाकिस्तान की मांग का मूल **दो-राष्ट्र सिद्धांत** में था, जिसे **सिर सैयद अहमद खान** ने 19वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग राष्ट्र हैं जिनकी धर्म, संस्कृति और सामाजिक रीतियाँ अलग हैं। यह सिद्धांत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ

में, विशेषकर **लखनऊ समझौते** (1916) के बाद प्रमुख हुआ, जब हिंदू और मुस्लिमों के बीच राजनीतिक सहयोग को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा गया।

- The **All India Muslim League**, founded in 1906, gradually became the platform for Muslim aspirations, and under **Jinnah's leadership**, it began to demand a separate nation for Muslims. This demand was formalized in 1940 with the passage of the **Lahore Resolution**, which called for the creation of Pakistan.
- **ऑल इंडिया मुस्लिम लीग**, जो 1906 में स्थापित हुई थी, धीरे-धीरे मुस्लिमों की आकांक्षाओं का मंच बन गई और **जिन्ना के नेतृत्व** में, यह मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगी। इस मांग को 1940 में **लाहौर प्रस्ताव** के पारित होने के साथ औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के निर्माण की बात की गई थी।

2. Reasons Behind the Demand for Pakistan:

- **Religious and Cultural Differences:** The primary reason for the demand for Pakistan was the perception that Hindus and Muslims had fundamentally different religions, cultures, and ways of life. Muslims feared that in a unified India, their religious, social, and political interests would be undermined by the Hindu majority.
- **धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताएँ:** पाकिस्तान की मांग का प्रमुख कारण यह धारणा थी कि हिंदू और मुसलमानों के धर्म, संस्कृति और जीवनशैली में मौलिक रूप से भिन्नताएँ हैं। मुसलमानों को डर था कि एक एकीकृत भारत में, उनकी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रुचियाँ हिंदू बहुलता द्वारा कमजोर कर दी जाएंगी।
- **Political Marginalization:** Muslims felt politically marginalized in the Congress-led struggle for independence, which was dominated by Hindu leaders. They believed that their interests and concerns were being sidelined in a predominantly Hindu-dominated India.
- **राजनीतिक हाशिए पर डालना:** मुसलमानों को कांग्रेस द्वारा नेतृत्व किए गए स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाले जाने का एहसास था, जिसमें हिंदू नेताओं का प्रभुत्व था। उनका मानना था कि एक प्रमुख हिंदू बहुल भारत में उनके हितों और चिंताओं को नजरअंदाज किया जाएगा।
- **Failure of Constitutional Safeguards:** The failure of previous constitutional arrangements, such as the **Montagu-Chelmsford Reforms** and the **Simon Commission**, to address Muslim concerns contributed to the demand for a separate nation.

- **संवैधानिक सुरक्षा उपायों की विफलता:** पूर्व संवैधानिक व्यवस्थाओं, जैसे **मोंटेगू-चेल्सफोर्ड सुधार** और **साइमन आयोग**, ने मुसलमानों की चिंताओं का समाधान नहीं किया था, जो पाकिस्तान के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग में योगदान कर रहे थे।

3. Consequences of the Demand for Pakistan:

- **Partition of India:** The demand for Pakistan culminated in the partition of India in 1947. The British, unable to resolve the differences between the Congress and the Muslim League, decided to divide India into two independent dominions: **India** and **Pakistan**.
- **भारत का विभाजन:** पाकिस्तान की मांग का परिणाम भारत के 1947 में विभाजन के रूप में हुआ। ब्रिटिशों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को हल न कर पाने के कारण भारत को दो स्वतंत्र राज्यों में विभाजित करने का निर्णय लिया: **भारत** और **पाकिस्तान**।
- **Communal Violence:** The partition led to widespread communal violence, with Hindus and Muslims fighting each other. Millions of people were displaced from their homes, and the migration from one country to another was marked by brutal massacres, rapes, and other atrocities.
- **सांप्रदायिक हिंसा:** विभाजन के परिणामस्वरूप व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे से लड़ रहे थे। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए, और एक देश से दूसरे देश में प्रवास के दौरान बेरहमी से हत्याएँ, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराध हुए।
- **Mass Migration:** The partition led to one of the largest mass migrations in history, with millions of Hindus and Sikhs migrating from Pakistan to India, and millions of Muslims migrating in the opposite direction. The migration was often accompanied by horrific violence and loss of life.
- **जन संचार:** विभाजन ने इतिहास के सबसे बड़े जनसंचारों में से एक को जन्म दिया, जिसमें लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत चले गए, और लाखों मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर प्रवासित हुए। इस प्रवास के दौरान भयंकर हिंसा और जीवन की हानि हुई।
- **Creation of Pakistan:** Pakistan was created as a separate nation for Muslims on **August 14, 1947**. It was initially divided into two regions: **West Pakistan** (modern-day Pakistan) and **East Pakistan** (now Bangladesh), separated by over 1,600 kilometers of Indian territory.

- **पाकिस्तान का निर्माण:** 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। इसे शुरू में दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: **पश्चिम पाकिस्तान** (वर्तमान पाकिस्तान) और **पूर्व पाकिस्तान** (अब बांग्लादेश), जो भारतीय क्षेत्र से 1,600 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित थे।
- **4. Impact on India and Pakistan: भारत और पाकिस्तान पर प्रभाव:**
 - **Increased Communal Tensions:** The partition not only created a new nation but also deepened communal tensions between Hindus and Muslims, which continue to affect relations between India and Pakistan even today.
 - **सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि:** विभाजन ने न केवल एक नया राष्ट्र बनाया, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनावों को भी बढ़ा दिया, जो आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित करते हैं।
 - **Economic and Political Setbacks:** Both countries faced significant economic and political challenges following partition. The division of assets, resources, and the impact of migration placed a heavy burden on both India and Pakistan.
 - **आर्थिक और राजनीतिक संकट:** विभाजन के बाद दोनों देशों को महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संपत्तियों, संसाधनों का विभाजन और प्रवास का प्रभाव भारत और पाकिस्तान दोनों पर भारी दबाव डाला।
 - **Relations Between India and Pakistan:** The partition and the creation of Pakistan laid the foundation for decades of hostility between India and Pakistan, resulting in multiple wars, territorial disputes, and a long-standing rivalry that continues to shape the political dynamics of South Asia.
 - **भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध:** विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण ने भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों तक शत्रुता की नींव रखी, जिसके परिणामस्वरूप कई युद्ध, क्षेत्रीय विवाद और लंबे समय तक प्रतिद्वंद्विता हुई, जो आज भी दक्षिण एशिया की राजनीतिक गतिशीलता को आकार देती है।

GOVERNMENT OF INDIA 1935

The **Government of India Act, 1935** was a major legislative step towards self-government for India. It was based on the recommendations of the **Simon Commission**, the **Round Table Conferences**, and the **White Paper of 1933**. The Act introduced significant changes to the political structure of British India, aiming to give more autonomy to Indian provinces and allow for greater Indian participation in the administration.

However, it did not grant full independence to India, and many Indian leaders considered it a limited measure that fell short of their demands for complete self-rule. The Act laid the groundwork for the future struggle for independence.

1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम था। यह **साइमन आयोग**, **राउंड टेबल सम्मेलन**, और **1933 के श्वेत पत्र** की सिफारिशों पर आधारित था। इस क़ानून ने ब्रिटिश भारत की राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देना और प्रशासन में भारतीय भागीदारी को बढ़ाना था।

हालांकि, इस क़ानून ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी, और कई भारतीय नेताओं ने इसे सीमित उपाय माना, जो पूर्ण स्वशासन की उनकी मांगों के अनुरूप नहीं था। यह अधिनियम स्वतंत्रता की आगामी संघर्ष के लिए आधार तैयार करने में सहायक था।

1. Federal System of Government:

- The Act introduced a **federal structure** for India, with a **central government** and **provincial governments**. It provided for a **Federation of India**, comprising British India and the princely states (if they agreed to join). However, the federation never came into being because the princely states did not agree to join the federation.
- इस क़ानून ने भारत के लिए एक **संघीय संरचना** की शुरुआत की, जिसमें **केंद्रीय सरकार** और **राज्य सरकारें** शामिल थीं। इसने भारत का एक **संघ** बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें शामिल थीं (यदि वे इसमें शामिल होने के लिए सहमत होते)। हालांकि, संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतें संघ में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुईं।

2. Provincial Autonomy:

- It provided provinces with a degree of autonomy, allowing them to have their own legislative assemblies and control over several subjects, except for those under the central government. Provinces were given the right to elect their own governments, though the central government retained the power to dismiss provincial governments.
- इसने प्रांतों को एक हद तक स्वायत्तता प्रदान की, जिससे वे अपनी विधानसभाएँ बना सकते थे और केंद्रीय सरकार के अंतर्गत न आने वाले कई मामलों पर नियंत्रण रख सकते थे। प्रांतों को अपनी सरकारें चुनने का अधिकार दिया गया, हालांकि केंद्रीय सरकार के पास प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार था।

3. Bicameral Legislature:

- The **Central Legislative Assembly** had two houses: the **Council of States** (upper house) and the **Legislative Assembly** (lower house). Members of the Legislative Assembly were elected through indirect elections, while the members of the Council of States were mostly appointed. The **Viceroy's Executive Council** was enlarged, with certain seats being made available for Indian members, including one for the **Secretary of State** for India.
- **केंद्रीय विधायी सभा** में दो सदन थे: **राज्य परिषद** (ऊपरी सदन) और **विधानसभा** (निचला सदन)। विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से चुने जाते थे, जबकि राज्य परिषद के सदस्य मुख्य रूप से नियुक्त किए जाते थे। **वाइसरॉय का कार्यकारी परिषद** को विस्तृत

किया गया, जिसमें भारतीय सदस्यों के लिए कुछ सीटें बनाई गईं, जिनमें **भारत के सचिव** के लिए एक सीट भी थी।

4. Separate Electorates and Communal Representation:

- The Act continued the **separate electorates** system, which gave different communities (Hindus, Muslims, Sikhs, etc.) the right to elect their own representatives to the legislative bodies. This provision aimed to safeguard the interests of the minority communities, but it deepened communal divisions in India.
- इस क़ानून ने **अलग-अलग निर्वाचन मंडल** प्रणाली को जारी रखा, जिससे विभिन्न समुदायों (हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि) को अपनी प्रतिनिधि विधानसभाओं में चुनने का अधिकार मिला। यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करने के लिए था, लेकिन इसने भारत में सांप्रदायिक विभाजन को गहरा किया।

5. Office of the Governor-General:

- The Governor-General continued to be the representative of the British Crown in India and had extensive powers. The Governor-General retained the authority to act without the advice of the Executive Council in certain matters, which limited the autonomy of the Indian government.
- गवर्नर-जनरल भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बना रहा और उसके पास व्यापक शक्तियाँ थीं। गवर्नर-जनरल को कुछ मामलों में कार्यकारी परिषद की सलाह के बिना कार्य करने का अधिकार था, जिससे भारतीय सरकार की स्वायत्तता सीमित हो गई।

6. Reserved Subjects:

- Certain subjects, such as defense, foreign affairs, and finance, were reserved for the central government. These were areas where the central government could exercise full control.
- कुछ मामलों जैसे रक्षा, विदेश नीति, और वित्त को केंद्रीय सरकार के लिए आरक्षित कर दिया गया था। ये वे क्षेत्र थे जहाँ केंद्रीय सरकार पूर्ण नियंत्रण का अभ्यास कर सकती थी।

7. Fundamental Rights and Laws:

- The Act introduced some **fundamental rights** for the Indian population, such as freedom of speech and religion, though these were limited in scope compared to those in a modern democracy. It allowed for the **separation of powers** between the executive, legislative, and judiciary, though the judicial independence was still limited.
- इस क़ानून ने भारतीय जनता के लिए कुछ **मूल अधिकार** पेश किए, जैसे बोलने और धर्म की स्वतंत्रता, हालांकि ये आधुनिक लोकतंत्रों की तुलना में सीमित थे। इसने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच **शक्ति का पृथक्करण** करने की अनुमति दी, हालांकि न्यायिक स्वतंत्रता अभी भी सीमित थी।

8. Electoral Reforms:

- The Act expanded the electorate in India by granting voting rights to a larger portion of the population. However, the voting system was still limited to those who met property qualifications, making it inaccessible to a large portion of the Indian populace.
- इस क़ानून ने भारत में मतदाता सूची का विस्तार किया और अधिक जनसंख्या को मतदान का अधिकार दिया। हालांकि, मतदान प्रणाली अभी भी उन तक सीमित थी जो संपत्ति योग्यता को पूरा करते थे, जिससे भारत की बड़ी जनसंख्या के लिए यह पहुंच से बाहर था।

FOR PDF VISIT MY WEBSITE

[Hindustanknowledge.com](https://hindustanknowledge.com) on google and download now

Join whatsapp channel for pdf links and live class updates

Links are in description

Scholarly Minds